कोरोना को लेकर केंद्र सरकार ने 15 हजार करोड़ के फंड का प्रावधान किया

नई दिल्ली, 25 मार्च (ए)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य सेवाओं को राज्य सरकारों की एकमात्र प्राथमिकता बताते हुए मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण से पैदा संकट से निपटने के लिये 15 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर एक सप्ताह से भी कम समय में राष्ट्र के नाम अपने दूसरे संदेश में मोदी ने कहा कि कोरोना से जुड़ी जांच की सुविधा, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, आईसीयू बिस्तर, वेंटिलेटर और अन्य जरूरी संसाधनों की संख्या तेजी से बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिये देश के स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे को और मजबूत बनाने के लिए 15 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

मोदी ने कहा, '' मैंने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि इस समय उनकी पहली प्राथमिकता, सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य सेवाएं ही होनी चाहिए। उन्होंने लोगों से कोरोना वायरस को लेकर अफवाह और अंधविश्वास से बचने की सलाह दी और कहा कि इस बीमारी के लक्षणों के दौरान बिना डॉक्टरों की सलाह के कोई भी दवा न लें। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि किसी भी तरह का खिलवाड़, आपके जीवन को और खतरे में डाल सकता है।

इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि शेयर बाजारों के उतार-चढ़ाव और घटनाक्रमों पर बाजार नियामक, वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक लगातार नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि शेयर बाजार और दूसरी वित्तीय बाजारों की स्थिति की दिन में तीन बार समीक्षा की जाती है। सीतारमण ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित रखने के लिए किए गए लॉकडाउन से हो रही परेशानियों से निपटने के लिए सरकार एक आर्थिक राहत पैकेज देने पर विचार कर रही है। इसके बारे में जल्द घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार और रिजर्व बैंक सहित दूसरे नियामकों की बाजार की स्थिति पर लगातार नजर है। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने बाजार की स्थिति को देखते हुए कुछ दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि उन्हें लोगों से भी कई सुझाव प्राप्त हुए हैं, सरकार उन पर भी ध्यान दे रही है।

उल्लेखनीय है कि देश में कोरोना वायरस के फैलने के बाद से शेयर बाजार में लगातार गिरावट का रुख बना हुआ है। बंबई शेयर बाजार का सूचकांका पिछले कुछ दिनों में 42,000 अंक से अधिक की ऊंचाई से लुढ़कता हुआ 26,000 अंक के आसपास आ चुका है। सोमवार को एक ही दिन में इसमें 3,900 अंक की गिरावट दर्ज की गई। वहीं अमेरिकी डालर के मुकाबले रुपए में भी बदस्तूर गिरावट का दौर जारी है। पिछले कुछ सप्ताह में यह 72 रुपए प्रति डालर से कमजोर पड़ता हुआ 76 रुपए से प्रति डालर से भी नीचे पहुंच चुका है।

आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर है सरकार की नजरः पासवान

नई दिल्ली, 25 मार्च (ए)। सरकार 21 दिनों के देशव्यापी लॉकडाउन के बीच आम लोगों को आश्वस्त करने में जुटी है कि इस दौरान आवश्यक वस्तुओं का अभाव नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि सरकार मार्केट में अनिवार्य वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्यों से भी संपर्क कर सुनिश्चित किया जा रहा है कि जरूरी सामानों की कमी नहीं हो।

पासवान का आश्वासनः पासवान ने ट्वीट कर बताया, सरकार कोरोना कोविड 19 इंडिया के खतरे से उत्पन्न स्थिति में तमाम आवश्यक वस्तुओं की बाजार में उपलब्धता पर लगातार नजर बनाए हुए है और सभी राज्य सरकारों के संपर्क में है ताकि कहीं भी किसी चीज की किल्लत न हो। उन्होंने व्यापारियों, दुकानदारों से भी ऊंची कीमत वसूलने को लेकर हिदायत दी। पासवान ने लिखा, सभी उत्पादकों और व्यापारियों से भी अपील है कि इस घड़ी में मुनाफाखोरी से बचें। केंद्र सरकार ने 23 मार्च को राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को भारतीय खाद्य निगम से तीन महीने का अनाज अडवांस में उठाने की अनुमति दे दी ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबों को पर्याप्त मात्रा में राशन दिया जा सके। अभी पीडीएस के तहत 75 करोड़ परिवारों को सस्ते राशन का लाभ मिलता है। अभी सरकार के पास 4.35 करोड़ टन अतिरिक्त अनाज जमा है जिनमें 27 करोड़ 21 लाख 90 हजार टन चावल और 16 करोड़ 27 लाख 90 हजार टन गेहूं का भंडार है।

हॉस्पिटल, हेल्पलाइन... कोरोना से जुड़ी हर मदद यहांः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा करते हुए भी कहा था कि इस दौरान जरूरी सामानों की कमी नहीं होने दी जाएगी। केंद्र सरकार ने 21 मार्च को छह राज्य के स्थानीय निकायों के लिए 2,570 करोड़ रुपये रिलीज कर दिए थे।

मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन के निर्यात पर प्रतिबंध

नयी दिल्ली, 25 मार्च (ए)। सरकार ने बुधवार को कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर घरेलू बाजार में दवा की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया। भारतीय चिकित्सा शोध परिषद (आईसीएमआर) के महानिदेशक बलराम भार्गव ने सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के संदिग्ध या पुष्ट मामलों में देखभाल करने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के इलाज के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन के इस्तेमाल की सिफारिश की थी। आईसीएमआर द्वारा कोविड-19 पर गठित राष्ट्रीय कार्यबल द्वारा की गई इलाज की सिफारिशों को भारतीय दवा महानियंत्रक (डीजीसीआई) ने आपातकालीन स्थितियों में प्रतिबंधित उपयोग के लिए मंजूरी दी है। वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की बुधवार को जारी एक अधिसूचना में कहा गया, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन बनाने वाले घटकों के निर्यात को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है।

जेके टायर के वरिष्ठ अधिकारी, बोर्ड सदस्य 25 प्रतिशत तक कम वेतन लेंगे

नई दिल्ली, 25 मार्च (ए)। कोरोना वायरस संकट के बीच जे.के. टायर एंड इंडस्ट्रीज के निदेशक मंडल के सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी 25 प्रतिशत तक कम वेतन लेंगे। कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक रघुपति सिंघानिया ने एक बयान में कहा, '' कोरोना वायरस संकट की वजह से मौजूदा वक्त में हम बिक्री और लाभ दोनों स्तर पर अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहे हैं।'' उन्होंने कहा कि इस मुश्किल वक्त में सहृदयता दिखाते हुए हमारा प्रबंधन और वरिष्ठ अधिकारी आगे आए हैं और उन्होंने अपना 25 प्रतिशत तक कम वेतन लेने का निर्णय किया है। सिंघानिया ने कहा, ''कंपनी के चेयरमैन और पूर्णकालिक निदेशक अपने वेतन से 25 प्रतिशत कम वेतन लेंगे जबकि वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी भी अपने वेतन से 15 से 20 प्रतिशत कम वेतन लेंगे।'' उन्होंने कहा कि वेतन में यह कटौती कंपनी के वैश्विक परिचालन के अधिकारियों पर भी लागू होगी। बीएस 6 हुंडई एलीट आई20 लॉन्च, शुरुआती कीमत 6.50 लाख रुपए, कंपनी ने डिस्कंटीन्यू किया डीजल वैरिएंट

नई बीएस 6 एलीट आई20 में अब सिर्फ चार वैरिएंट में अवेलेबल होगी

नई दिल्ली, 25 मार्च (ए)। हुंडई ने एलीट आई20 हैचबैक का बीएस6 मॉडल लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.50 लाख रुपए है। यह प्रीमियम हैचबैक अब सिर्फ पेट्रोल-मैनुअल वर्जन में ही मिलेगी। कंपनी ने इसके 1.4 लीटर डीजल इंजन और सीवीटी ऑटोमैटिक ऑप्शन को बंद कर दिया है। नई बीएस6 एलीट आई20 में अब सिर्फ चार वैरिएंट में अवेलेबल होगी।

इंजनः इंजन की बात करें तो इसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है जो 83 हॉर्स पावर की ताकत और 114 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। कार में स्टैंडर्ड तौर पर 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स ट्रांसमिशन मिलेगा। बीएस6 अपग्रेशन के बाद कार पहले से 15 हजार रुपए तक महंगी हो गई है।

अमेरिका में संघीय अधिकारियों के बीच 2000 अरब डॉलर के राहत पैकेज पर सहमति बनी

वाशिंगटन, 25 मार्च (ए)। अमेरिका में व्हाइट हाउस और संसद के दोनों दलों के नेताओं के बीच अर्थव्यवस्था को 2000 अरब डॉलर का राहत पैकेज देने पर सहमति बन गई है। इस पैकेज का मकसद कर्मचारियों, कारोबारियों और स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूती देना है। शीर्ष व्हाइट हाउस के सहायक एरिक उलैंड ने आधी रात के तुरंत बाद कैपिटल हॉलवे में समझौते की घोषणा की। उलैंड ने कहा, देवियों और सज्जनों, हम कामयाब रहे। समझौता हो गया है। इस अभूतपूर्व आर्थिक राहत पैकेज से ज्यादातर अमेरिकियों को प्रत्यक्ष भुगतान किया जाएगा, बेरोजगारी लाभ का विस्तार होगा और छोटे कारोबारियों के 367 अरब डॉलर का सहायता कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, ताकि घर में रहने के दौरान श्रमिकों को वेतन का भुगतान किया जा सके। इसके अलावा विमानन और स्वास्थ्य सेवा जैसे बड़े क्षेत्रों के लिए भी विशेष पैकेज का प्रावधान किया जाएगा।

ई कामर्स फिसड्डी, पड़ोस की दुकान पर मिल रहा है ज्यादा सामान

नयी दिल्ली, 25 मार्च (ए)। कोरोना वायरस की वजह से हुए देशभर में हुए लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तु उपलब्ध कराने में ई-कॉमर्स ऐप फिसड्डी साबित हुए हैं। इनके यहां न सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता घट गई है बल्कि सामान की डिलिवरी भी समय पर नहीं हो रही है। इन ऐप्स की तुलना में पड़ोस के दुकानदार के यहां ज्यादा सामान मिल रहा है और ग्राहक हाथोंहाथ सामान ले पा रहे हैं। इसका खुलासा लोकल सर्किल के एक सर्वे से हुआ है।

यह सर्वे देश के 164 से भी ज्यादा जिलों में किया गया, जिसमें 16000 से भी ज्यादा प्रतिभागी शामिल हुए। लोकल सर्किल ने इस सर्वे को दो हिस्से में बांट कर किया। पहला बीते 20 से 22 मार्च के बीच जबकि दूसरा 23 से 24 मार्च के बीच। पहली अवधि के दौरान ई कामर्स ऐप पर 35 फीसदी ग्राहकों को आटा, चावल, दाल, नमक, चीनी जैसी आवश्यक वस्तुएं नहीं

मिलीं जबकि पड़ोस के दुकानदार के मामले में यह 17 फीसदी था। दूसरी अवधि में ऐप पर जहां 79 फीसदी ग्राहकों को आवश्यक सामान नहीं मिला, वहीं पड़ोस की दुकान जाने पर महज 32 फीसदी ग्राहकों को ही निराश होना पड़ा। शेष ग्राहकों को सामान मिल गया।

समय पर नहीं हो रही है डिलिवरीः सर्वे में निकलकर आया कि पिछले दो दिनों के दौरान ऐप ने महज 21 फीसदी ग्राहकों को ही समय पर आवश्यक सामानों की आपूर्ति की। 27 फीसदी ग्राहकों का कहना था कि उन्हें सामानों की डिलिवरी के लिए लंबा समय दिया गया। 21 फीसदी ग्राहकों को पूरा नहीं, बल्कि कुछ ही सामानों की डिलिवरी मिली जबकि 14 फीसदी को देर से डिलिवरी मिली। 17 फीसदी ग्राहकों का तो ऑडर कैंसल कर दिया गया।

पड़ोस की दुकान में है ज्यादा सामानः सर्वेक्षण में शामिल लोगों में से 38 फीसदी प्रतिभागियों का कहना है कि पड़ोस की दुकान पर दैनिक उपयोग की सभी वस्तुएं आसानी से उपलब्ध हैं। 30 फीसदी लोगों का कहना था कि कुछ सामानों को छोड़ दिया जाए तो उन्हें सब सामान मिल गया। 12 फीसदी ग्राहकों को वहां कुछ ही सामान मिला जबकि 15 फीसदी प्रतिभागियों ने कहा कि उन्हें दुकान में अधिकतर सामान नहीं मिला। पांच फीसदी लोगों ने कहा कि उन्हें जरूरत का कोई भी सामान नहीं मिला।

ऐसा हो तो स्थिति सुधरेः लोकल सर्किल का कहना है कि सरकार को ई कॉमर्स प्लैटफार्मों और संगठित खुदरा विक्रेताओं को ऐसे निर्देश देने चाहिए कि वह सुपर स्टॉकिस्ट, वितरकों और सभी विक्रेताओं को इस समय अलग से कर्मचारी तैनात करे जो कि आवश्यकत वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करे।

35 प्रतिशत से 79 प्रतिशत उपभोक्ताओं को समय में पर जरूरी सामान की डिलिवरी नहीं मिल पा रही है

लोकल सर्किल के मुताबिक, 17 प्रतिशत ने कहा उनका ऑॅर्डर रद्द हुआ, 21 प्रतिशत ने कहा कि जरूरी ऑॅर्डर हुए डिलिवर कान

17 प्रतिशत से 32 प्रतिशत उपभोक्ता रिटेल दुकानों में सामान खोजने में हो रही परेशानी

48 घंटों के दौरान ई –कॉमर्स पर ऐप ग्राहकों का अनुभव, 14 प्रतिशत ने कहा उनके ऑॅर्डर में देरी

लॉकडाउन से रियल एस्टेट सेक्टर में ऑनलाइन सर्च बढ़ी

नई दिल्ली, 25 मार्च (ए)। कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ने के बाद पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो गई है। अधिकांश कामकाजी लोग घरों से कार्य कर रहे हैं। जो लोग काम नहीं कर रहे हैं वह इंटरनेट पर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। इसका फायदा रियल एस्टेट सेक्टर को हो रहा है। दिल्ली-एनसीआर के कई डवलपर्स का कहना है कि कोरोनावायरस फैलने और लॉकडाउन के बाद हाउसिंग सेक्टर में ऑनलाइन सर्च बढ़ गई है। इस मौके का फायदा उठाने के लिए डवलपर्स भी खरीदारों के साथ संवाद करने और अपनी योजनाओं, ऑफर और इस तरह के अन्य विवरणों को एसएमएस, व्हाट्सएप, मेल और कॉलिंग के माध्यम से अधिकतम लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रभावी तरीके अपना रहे हैं।

घर से काम करने के कारण लोगों को मिल रहा ज्यादा समयः सनवर्ल्ड ग्रुप के सीईओ विजय वर्मा का कहना कि कोरोना के कारण अधिकांश लोग घर से काम कर रहे हैं। इससे लोगों को ऑनलाइन प्रॉपर्टी सर्च करने के लिए लेने के लिए अधिक समय मिल रहा है और क्षेत्र व प्रॉपर्टी के बारे में अच्छे से शोध कर रहे है। हालांकि, वे साइटों का दौरा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि हालात बेहतर होने के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में बिक्री बढ़ेगी। वेल्थ क्लीनिक के सीएमडी अमित रहेजा के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में ऑनलाइन और टेलीफोन पर पूछताछ में खासा इजाफा हुआ है। उन्होंने उम्मीद जताई की हालात सामान्य होने के बाद पूछताछ करने वाले सामने आएंगे और खरीदारी करेंगे।

रियल एस्टेट सेक्टर पर कोरोना के प्रभाव का अनुमान लगाना जल्दबाजीः महागुन ग्रुप के डायरेक्टर धीरज जैन का कहना है कि रियल एस्टेट सेक्टर पर किसी भी तरह के प्रभाव का अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी। धीरज जैन के अनुसार, यह घर खरीदने का सबसे अच्छा समय है, क्योंकि प्रॉपर्टी की कीमतें मौजूदा समय में काफी प्रतिस्पर्धी हैं और ब्याज दरें भी कम हैं। इसके अलावा पिछले पांच वर्षों में नोएडा समेत अधिकांश प्रमुख रियल्टी बाजारों में कीमतों में गिरावट आई है या मामूली रूप से बढ़ी है। हालांकि, अगर कोरोनावायरस का प्रभाव लंबे समय तक रहता है तो रियल एस्टेट सेक्टर में विशेष रूप से कमर्शियल और रिटेल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस सेक्टर को कुछ रियायतें प्रदान करेगी। इसके अलावा पहले से तनावग्रस्त इंडस्ट्री पर कर्ज को नरम करने के लिए एक बार के पुनर्गठन पर विचार किया जाना चाहिए।

लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था को 120 अरब डॉलर का नुकसान

नई दिल्ली, 25 मार्च (ए)। कोरोनावायरस की वजह से देशभर में लॉकडाउन का अर्थव्यवस्था को करीब 120 अरब डॉलर की कीमत चुकानी होगी। यही नहीं, इस वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर भी घट जाएगी। यह हिसाब बार्कलेज बैंक ने अपनी एक रिसर्च रिपोर्ट में लगाया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलवार शाम को दिए गए राष्ट्र के नाम संदेश के बाद तैयार इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बदली परिस्थितियों के मद्देनजर, कैलेंडर वर्ष 2020 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर महज 2.5 फीसदी रह जाएगी जबकि पहले का अनुमान 4.5 फीसदी का था। इसके साथ ही वित्त वर्ष 2020–21 के लिए विकास दर के पूर्वानुमान को 5.2 फीसदी से घटा कर 3.5 फीसदी कर दिया है।

अलगे वर्ष बढ़ेगी तेजीः चालू साल में भले ही विकास दर घटे, लेकिन अगले साल इसमें बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है। बार्कलेज ने कैलेंडर वर्ष 2021 के लिए सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी में 8.2 फीसदी की बढोतरी का अनुमान लगाया है जबकि वित्त वर्ष 2021–22 के लिए 8.0 फीसदी का।

लॉकडाउन से घाटाः रिपोर्ट का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को करीब 120 अबर डॉलर का नुकसान होगा, जो कि जीडीपी का चार फीसदी है। इनमें से 90 अरब डॉलर का नुकसान को लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की वजह से होगा। जाहिर है कि इसका असर जीडीपी की विकास दर पर भी पड़ेगा।

इससे पहले इन्होंने भी घटाया अनुमानः कुछ दिन पहले ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस इंडिया ने 2020-21 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को घटा कर चार फीसदी कर दिया था जबकि पहले इसके 5.1 फीसदी रहने का अनुमान जताया गया था। इसके अलावा, फिच मौजूदा वित्त वर्ष के लिए तष्ठक्क अनुमान को 5.6 से घचाकर 5.1 पर्सेंट कर चुकी है। मूडीज ने इसे 5.4 से घटाकर 5.3 पर्सेंट कर दिया था और एस ऐंड पी ग्लोबल ने इसे पहले दए 5.7 पर्सेंट के अनुमान से घटाकर 5.2 पर्सेंट कर दिया था।

लॉकडाउन के दौरान 21 दिन तक अस्थायी रूप से बंद रहेगी फ्लिपकार्ट, लोगों से घरों में रहने की अपील

नई दिल्ली, 25 मार्च (ए)। देश की प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने लॉकडाउन को देखते हुए अपनी सेवा बंद करने का फैसला किया है। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर एक एडवाइजरी जारी कर कहा है कि लॉकडाउन के दौरान 21 दिनों तक उसकी सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहेंगी। कंपनी ने कहा है कि हम अस्थायी रूप से अपनी सेवाएं बंद कर रहे हैं। यह एडवाइजरी कंपनी की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित हो रही है।

लोगों से घरों में रहने की अपीलः कंपनी की ओर से जारी एडवाइजरी जारी कर कहा है कि हम आपकी आवश्यकता हमेशा हमारी प्राथमिकता रही है। कंपनी ने वादा किया है कि हम जितना संभव हो सकेगा, हम आपकी सेवा के लिए लौटकर आएंगे। फ्लिपकार्ट ने एडवाइजरी में कहा है कि यह एक मुश्किल समय है। ऐसा समय पहले कभी नहीं आया है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है कि लोगों ने घरों में रहकर देश की सेवा की है। ऐसे में आपसे अपील है कि आप घरों में रहे और सुरक्षित रहें। जानकारों का मानना है कि लॉकडाउन के दौरान डिलीवरी सेवा प्रभावित होने के कारण कंपनी ने यह फैसला लिया है।

पीएम ने किया है 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलानः कोरोनावायरस की रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार शाम 8 बजे अपने संबोधन में पूरे देश में 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के हर राज्य, हर जिले, हर कस्बे और हर मोहल्ले को लॉकडाउन किया जाएगा। 29 मिनट के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा- 'हिंदुस्तान को बचाने के लिए 21 दिन का यह लॉकडाउन बेहद

जरूरी है। यह जनता कर्फ्यू से ज्यादा सख्त होगा और यह एक तरह से कर्फ्यू ही है।' प्रधानमंत्री ने कहा कि 'बाहर निकलना क्या होता है, यह 21 दिन के लिए भूल जाइए। 21 दिन नहीं संभले तो आपका देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाएगा। कोरोना से मुकाबले के लिए सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। हमें संक्रमण के चक्र को तोड़ना होगा। कोरोना से तभी बचा जा सकता है, जब घर की लक्ष्मण रेखा ना लांघी जाए।'

भारत में 15 दिन में 11 लोगों की मौतः देश में कोरोनावायरस की स्थिति गंभीर होती जा रही है। संक्रमितों का आंकड़ा 500 पार कर गया। 15 दिन में संक्रमण से 11 लोगों की जान जा चुकी है। बुधवार सुबह मदुरै में 54 वर्षीय कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री सी विजय भास्कर ने कहा कि मरीज को लंबे समय से डायबिटीज और ब्लडप्रेशर की समस्या थी। तमिलनाडु में कोरोना से यह पहली मौत है। इससे पहले मंगलवार को महाराष्ट्र में एक संक्रमित की मौत हुई थी। यहां 63 साल के बुजुर्ग की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उन्हें भी पहले से हाई ब्लडप्रेशर की समस्या थी। अब तक जिन 11 लोगों की जान गई है, उनमें से 8 को शुगर या ब्लडप्रेशर की समस्या थी। पूरी दुनिया में कोरोना से अब तक 16 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।